राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका सं. **14949/2020**

कुमार इंदु भूषण, पुत्र स्वर्गीय गुरुदयाल साहू, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 189, अंजनी मार्ग, हनुमान नगर एक्सटेंशन, जयपुर, पूर्व में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के रूप में कार्यरत थे। (अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, शासकीय सचिवालय, जयपुर-302005 (राजस्थान) के माध्यम से।

3. सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर-302005 (राजस्थान) के माध्यम से।

4. अजीत सिंह, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, राजस्थान (सेवानिवृत्त), आवासीय पता: सी/ ओ कर्नल राज सिंह निवासी सूर्या निकेतन, सी-11, जय सिंह हाईवे, बानी पार्क, जयपुर, राजस्थान पिन-302016.

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित
प्रतिवादियों के लिए	:	श्री आनंद शर्मा, उनके साथ श्री नमनदीप सिंह श्री एस.एस. राघव, विद्वत एएजी

माननीय श्री न्यायमूर्ति पंकज भंडारी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड़

<u>आदेश</u>

आरक्षित करने की तारीख	:	12 अप्रैल, 2022
उच्चारित करने की तारीख	:	27 अप्रैल, 2022

रिपोर्टेबल

(**निर्णय**: **अनूप कुमार ढंड़**, **न्यायमूर्ति**)

याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका दायर करके केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर खंडपीठ, जयपुर (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.8.2020 को रद्द और निरस्त करने और अवर सचिव भारत सरकार, गृह मंत्रालय (पुलिस- I डिवीजन), नई दिल्ली द्वारा 29.3.2018 को जारी आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की है तथा प्रतिवादियों संख्या 1 से 3 को 06.04.2018 सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की है।

तत्काल याचिका को दायर करने के पीछे तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 21.8.1989 को भारतीय पुलिस सेवा (संक्षेप में 'आईपीएस') में शामिल हुआ। संस्थागत और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, याचिकाकर्ता को 18.11.1991 को सहायक पुलिस अधीक्षक (संक्षेप में 'एएसपी') के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 27.7.1993 को पुलिस अधीक्षक (वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को 18.3.1998 को पुलिस अधीक्षक (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद, उन्हें 28.3.2005 को पुलिस अधीक्षक (चयन वेतनमान) के पद पर पदोन्नत किया गया। फिर उन्हें पुलिस अधीक्षक (चयन वेतनमान) के पद से उपप्रधान के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें 5.4.2007 को पुलिस महानिरीक्षक और 5.7.2008 को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और 31.12.2013 को उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।

याचिकाकर्ता को अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 (संक्षेप में '1958 के नियम') के नियम 16(3) के तहत 29.3.2018 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी।

अपने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिनांक 29.3.2018 से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने मूल आवेदन संख्या 552/2018 दाखिल करके ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, जिसे दिनांक 07.8.2020 के आदेश के तहत उसके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिनांक 29.3.2018 को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया।

ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2020 और साथ ही भारत सरकार के

अवर सचिव, गृह मंत्रालय (पुलिस-I डिवीजन), नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.3.2018 से असंतुष्ट महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने यह तत्काल याचिका दायर की है। है।

याचिकाकर्ता ने इन आदेशों को यह कहते हुए चुनौती दी है कि दिनांक 29.3.2018 का आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 28.6.2012 के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों के तहत, केवल संदिग्ध ईमानदारी वाले व्यक्तियों को या ऐसे अधिकारियों, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, को ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि समीक्षा समिति द्वारा व्यक्तियों की एक सूची पर विचार किया गया था, जिसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले थे, जो प्रतिवादियों द्वारा उनकी बुद्धिमत्ता का पूरी तरह से प्रयोग न किया जाना दर्शाता है। समीक्षा समिति ने दिशा-निर्देशों की अनदेखी की है अर्थात आचरण तत्काल 5-6 वर्षों के लिए असंतोषजनक होना चाहिए लेकिन समिति ने याचिकाकर्ता के 'अच्छे' और 'बहुत अच्छे' एसीआर को 'औसत' और 'कमजोर' माना। दूसरों की एसीआर की तुलना की गई और फिर भी याचिकाकर्ता के खिलाफ ही आदेश पारित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी स्वतंत्र विचार के समीक्षा समिति की सलाह का पालन किया है, जो सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि को समीक्षा समिति को सौंपने के समान है, जो सही नहीं है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि समीक्षा समिति याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित थी जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि समिति के समक्ष कई मामले थे लेकिन उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव करते समय अकेले याचिकाकर्ता के मामले की विस्तार से जांच की।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि कई व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कदाचार/भ्रष्टाचार के गंभीर मामले थे, लेकिन उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि समीक्षा समिति ने उसके खिलाफ खिलाफ दर्ज एफआईआर को ध्यान में रखा है और चार एफआईआर में से दो मामलों को अंतिम नकारात्मक रिपोर्ट के साथ बंद कर दिया गया था और तीसरी एफआईआर में कोई चार्जशीट नहीं दी गई और चौथी एफआईआर अभी भी लंबित थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत

किया कि उसके खिलाफ कोई मकान किराया भत्ता बकाया नहीं था क्योंकि उसके पास कोई सरकारी आवास नहीं था, जैसा कि अधिकारियों ने आरोप लगाया है। तेलंगाना के राज्यपाल के साथ दुर्व्यवहार के आरोप सही नहीं थे क्योंकि अधिकारियों ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार पर भरोसा किया है। उन्होंने आगे कहा कि समीक्षा समिति द्वारा उनकी समय से पहले सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने के लिए जो आधार अपनाया गया है, वह प्रकृति में कलंकित है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 4-अजीत सिंह, तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, उनके खिलाफ व्यक्तिगत दुर्भावना रखते थे और वह उनके रास्ते में रोड़ा थे। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ उन दुर्भावनाओं से बाहर कार्रवाई की गई है।

अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की है:-

(1) श्यामलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एआईआर 1954 एससी 369 में रिपोर्ट किया गया;

(2) ब्रिज मोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1987 एससी 948 में रिपोर्ट किया गया;

(3) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चंद्र मोहन निगम और अन्य, एआईआर 1977 एससी 2411 में रिपोर्ट किया गया;

(4)भारत संघ एवं अन्य बनाम एम.ई. रेड्डी एवं अन्य, एआईआर 1980 एससी 563 में रिपोर्ट किया गया;

(5) बलदेव राज चड्ढा बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1981 एससी 70 में रिपोर्ट किया गया;

(6) बैकुंठ नाथ दास एवं अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा, एआईआर 1992 एससी 1029 में रिपोर्ट किया गया;

(7) म.प्र. राज्य सहकारी. डेयरी फेडरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम रजनेश कुमार जमींदार एवं अन्य, रिपोर्ट (2009) 15 एससीसी 221;

(8) गुजरात राज्य बनाम उमेदभाई एम. पटेल, एआईआर 2001 एससी 1109 में रिपोर्ट किया गया;

(9) साकीनाला हरि नाथ एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, 1993 (3) एएलटी

471 में रिपोर्ट किया गया;

(10) एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1997 एससी 1125 में रिपोर्ट किया गया;

(11) ज्ञान सिंह मान बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य, एआईआर 1980 एससी 1894 में रिपोर्ट किया गया;

(12) भारत संघ बनाम कर्नल जे.एन. सिन्हा एवं अन्य, एआईआर 1971 एससी 40 में रिपोर्ट किया गया;

(13) इलाहाबाद बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम इलाहाबाद बैंक और अन्य, एआईआर 1996 एससी 2030 में रिपोर्ट किया गया;

(14) पटना उच्च न्यायालय बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव और अन्य, एआईआर 2017 एससी 548 में रिपोर्ट किया गया;

(15) ए.एम. चौहान बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2006 (92) एसएलजे 303 (सीएटी) में रिपोर्ट किया गया;

(16) नंद कुमार वर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2006 (4) जेसीआर 560 (जेएचआर) में रिपोर्ट किया गया;

(17) शमीम अहमद लाहरवाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, 2017(2) जेकेजे 473 में रिपोर्ट किया गया;

(18) प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, एआईआर 2010 एससी 3753 में रिपोर्ट किया गया;

(19) आर.एल. बुटेल बनाम भारत संघ एवं अन्य, 1968 की सिविल अपील संख्या 1614 से 1616 में रिपोर्ट किया गया, 08/09/1969 को निर्णय लिया गया;

(20) एस.आर. वेंकटरमन बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1979 एससी 49 में रिपोर्ट किया गया;

(21) अनूप जयसवाल बनाम भारत सरकार एवं अन्य, एआईआर 1984 एससी 636 में रिपोर्ट किया गया;

(22) राम एकबाल शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, एआईआर 1990 एससी 1368 में

रिपोर्ट किया गया;

(23) डॉ. एस.एम. थिरुनावुक्करासु बनाम सरकार सचिव एवं अन्य, डब्ल्यू.पी. (एमडी) संख्या 10742, 2007में रिपोर्ट किया गया, 31/10/2008 को निर्णय लिया गया;

(24) ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, एआईआर 1974 एससी 555 में रिपोर्ट किया गया;

(25) भारत संघ एवं अन्य। वी. महेंद्र कुमार, (1985) आईआईएलजे 108 एपी में रिपोर्ट किया गया;

(26) बोडू तरमामद बनाम डीटी. उप अधीक्षक पुलिस, जामनगर एवं अन्य, (1988) 1 जीएलआर 101 में रिपोर्ट किया गया;

(27) गुजरात राज्य एवं अन्य बनाम सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह, (1999) 1 एससीसी 529 में रिपोर्ट किया गया;

(28) गुलाम मोहम्मद लोन बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, एसडब्ल्यूपी संख्या 166/2016 में रिपोर्ट किया गया, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने 05/10/2018 को निर्णय लिया;

(29) गोलम मोहिउद्दीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य, एआईआर 1964 कैल 503 में रिपोर्ट किया गया;

(30) ए.के. क्रेपक एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, एआईआर 1970 एससी 150 में रिपोर्ट किया गया;

(31) नरेश चंद्र शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2006) 3 एडब्ल्यूसी 2743 एआईआई में रिपोर्ट किया गया;

(32) राम मूर्ति यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एआईआर 2020 एससी 227 में रिपोर्ट किया गया;

(33) सचिव, प्रबंध समिति, बीएसएमपीजी कॉलेज, रूड़की बनाम सम्राट शर्मा एवं अन्य, (2019) 16 एससीसी 56 में रिपोर्ट किया गया;

(34) रूप सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, आरएलडब्ल्यू 2006 (4) 3323, राजस्थान में रिपोर्ट किया गया।

(35) राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम वेद प्रिया एवं अन्य, एआईआर 2020 एससी 2811 में

रिपोर्ट किया गया;

(36) ब्रिज बिहारी लाल अग्रवाल बनाम माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं अन्य, एआईआर 1981 एससी 594 में रिपोर्ट किया गया;

(37) जे.डी. श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, 1984 एआईआर 630 में रिपोर्ट किया गया;

(38) जगदीश मित्तर बनाम भारत संघ, सिविल अपील 718/1962, एससी में रिपोर्ट किया गया, 20/09/1963 को निर्णय लिया गया;

(39) राम चंदर बनाम हरियाणा राज्य, सीडब्ल्यूपी नंबर 26726/2016, पी एंड एच एचसी में रिपोर्ट किया गया, 01/03/2018 को निर्णय लिया गया;

(40) अरुण कुमार गुप्ता बनाम झारखंड राज्य, सीडब्ल्यूपी नंबर 190/2018, एससी में रिपोर्ट किया गया, 27/02/2020 को निर्णय लिया गया;

(41) राजेंद्र सिंह वर्मा बनाम दिल्ली के एनसीटी के उपराज्यपाल, सी.ए. में रिपोर्ट किया गया। क्रमांक 7781/2011, एससी, निर्णय 12/09/2011;

(42) भारत संघ बनाम वी.पी. सेठ, एआईआर 1994 एससी 1261 में रिपोर्ट किया गया;

(43) के. कंडास्वामी बनाम भारत संघ, 1996 एआईआर 277 में रिपोर्ट किया गया;

(44) लक्ष्मी दास शेट्टी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, 1988 एआईआर 1274 में रिपोर्ट किया गया;

(45) सुरिंदर सिंह बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य, 1986 एआईआर 2166 में रिपोर्ट किया गया;

(46) श्रीमती कबूतरा देवी बनाम यूपी राज्य, सर्विस सिंगल नंबर 30385/2017 एआईआई में रिपोर्ट किया गया, एचसी (लखनऊ बेंच), 03/09/2019 को निर्णय लिया गया;

(47) के.एम. शनमुगम बनाम एस.आर.वी.एस. प्रा. लिमिटेड एवं अन्य, 1963 एआईआर 1626 में रिपोर्ट किया गया;

(48) रामपुर डिस्टिलरी कंपनी बनाम कंपनी लॉ बोर्ड, 1970 एआईआर 1789 में रिपोर्ट किया गया;

(49) रंजीत सिंह आदि बनाम भारत संघ, 1981 एआईआर 461 में रिपोर्ट किया गया;

(50) डॉ. एस.पी. कपूर आदि बनाम एच.पी. राज्य, 1981 एआईआर 2181 में रिपोर्ट किया गया;

(51) वाई.एन. कृष्णा मूर्ति बनाम कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन, आईएलआर 1997 केएआर 1768 में रिपोर्ट किया गया;

(52) एस.आर. उपाध्याय बनाम राज्य, डब्ल्यूपीएस नंबर 2488/2015 में रिपोर्ट किया गया, छत्तीसगढ़ एचसी, 02/03/2017 को निर्णय लिया गया; और

(53) कामता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, डब्ल्यूपी संख्या 6487/1992 (एस.बी.), सभी में रिपोर्ट किया गया, एचसी, 23/03/1993 को निर्णय लिया गया।

उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि समीक्षा समिति के समक्ष सभी सामग्री नहीं रखी गई थी। समीक्षा समिति के पास अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए, जिसका वर्तमान मामले में अभाव है। अंत में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दिनांक 7.8.2020 के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए और ट्रिब्यूनल के सदस्यों की निंदा की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 7.8.2020 के आदेश के तहत पसंदीदा मूल आवेदन संख्या 552/2018 को खारिज करते समय ट्रिब्यूनल द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और साथ ही, दिनांक 29.3.2018 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए प्रतिवादियों द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है जिसके द्वारा उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई थी।

प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा आगे कहा है कि प्रतिवादियों द्वारा पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश याचिकाकर्ता के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद समीक्षा समिति द्वारा लिया गया एक स्वतंत्र निर्णय है, समिति की राय थी कि याचिकाकर्ता की प्रतिवादियों की सेवा में लंबे समय तक बने रहना उपयोगी नहीं रहेगा।

प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों के साथ याचिकाकर्ता की सेवाओं को जारी रखना सार्वजनिक हित में है। याचिकाकर्ता के आचरण ने उसे किसी भी सार्वजनिक पद पर तैनात करने के विभाग के विश्वास को समाप्त कर दिया है, जिसमें सार्वजनिक व्यवहार भी शामिल

है जो प्रकृति में संवेदनशील है। इस प्रकार, समीक्षा समिति ने माना कि सेवाओं में उनका बने रहना जनता और सामान्य प्रशासन के लिए भी उपयोगी नहीं होगा। याचिकाकर्ता का आचरण सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय और सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है और सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता में बाधा डालता है।

यह भी कहा गया है कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश याचिकाकर्ता के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड के आधार पर समीक्षा समिति द्वारा लिया गया बिल्कुल स्वतंत्र निर्णय है और समीक्षा समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि याचिकाकर्ता को 1958 के नियमों के नियम 16(3) के तहत जनहित में सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि यह न्यायालय समीक्षा समिति के फैसले के खिलाफ अपील में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और प्रतिवादियों की ओर से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करते हुए न तो कोई दुर्भावना व्यक्त की गई है और न ही प्रतिवादियों की ओर से कोई मनमानी की गई है।

प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न तो कलंकपूर्ण है और न ही इसका कोई नागरिक परिणाम होता है और इसलिए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी सरकारी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है और न ही उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

अधिवक्ताओं ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी था था और 29.3.2018 को अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पारित करने के समय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का पद संभाल रहा था। उसके बार-बार अप्राकृतिक आचरण के कारण सरकार को ऐसा आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर के के पद से स्थानांतरित होने पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने तेलंगाना के राज्यपाल के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और यह तथ्य 21 नवंबर को एक राष्ट्रीय समाचार पत्र 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में रिपोर्ट किया गया था। उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता ने तत्कालीन डी.जी. डी.जी. कारागार के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था जब उसे समय पर कार्यालय आने के लिए कहा गया। और इस याचिका पर बहस के दौरान भी याचिकाकर्ता ने ने दलील दी है कि ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारियों ने विवादित आदेश पारित करते समय

समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अंत में, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस याचिका पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जा सकता है।

अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने ***के. कांडा स्वामी बनाम भारत संघ (1995) 6 एससीसी 162 में रिपोर्ट किया गया, निशा प्रिया भाटिया बनाम भारत संघ (2020) 13 एससीसी 56 में रिपोर्ट किया गया और*** राम मूर्ति यादव (सुप्रा*)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.8.2020 के आदेश के तहत मूल आवेदन संख्या 552/2018 को खारिज करते समय कोई त्रुटि नहीं की गई है और ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 29.3.2018 को पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है।

हमने याचिकाकर्ता को, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और ऊपर उद्धृत निर्णयों सहित हमें उपलब्ध कराई गई संपूर्ण सामग्री का भी अध्ययन किया है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से बैकुंठनाथ दास और अन्य (सुप्रा) के निर्णयों की श्रृंखला में विचार किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है, लेकिन इसके फलस्वरूप कोई कलंक या दुर्व्यवहार का कोई संकेत नहीं है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सार्वजनिक हित में है और सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया गया है और इसे इस न्यायालय द्वारा केवल इस कारण से रद्द नहीं किया जा सकता है कि कर्मचारी को पदोन्नति दी गई थी।

इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बैकुंठ नाथ दास (सुप्रा) के पैरा-12, 33, 34 और 36 में निम्नानुसार माना है: -

> "12. *वर्ष* 1970 *में, इस न्यायालय की, एक खंडपीठ जिसमें जे.सी. शाह और के.एस. हेगड़े, जे.जे. शामिल थे, ने भारत संघ बनाम जे.एन. सिन्हा* [(1970) 2 *एससीसी* 458: (1971) 1 *एससीआर* 791] *में यह निर्णय दिया कि एफ.आर.* 56(*जे*)*के तहत जारी किए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति*

केआदेश में कोई नागरिक परिणाम शामिल नहीं है, क्योंकि इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले उसके द्वारा अर्जित किसी भी अधिकार को नहीं खोता है और उक्त नियम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है। यह बताया गया कि उक्त नियम संविधान के अनुच्छेद 310 *में सन्निहित आनंद सिद्धांत के पहलुओं में से एक का प्रतीक है और यह नियम व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी के अधिकारों और जनता के हित के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह व्याख्या की गई थी कि इस नियम का उद्देश्य, सरकार को अपने तंत्र को सक्रिय करने और उन लोगों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करके कुशल बनाने में सक्षम बनाना है, जिन्हें उसकी राय में सार्वजनिक हित में सेवा में नहीं होना चाहिए। यह भी माना गया कि ऐसे मामले में प्राकृतिक न्याय के नियम लागू नहीं होते। यह माना गया कि यदि उपयुक्त प्राधिकारी अपेक्षित राय प्रामाणिक रूप से बनाता है, तो उसकी राय को अदालतों के समक्ष चुनौती चुनौती नहीं दी जा सकती है, हालांकि पीड़ित पक्ष यह तर्क देने के लिए खुला खुला है कि अपेक्षित राय नहीं बनाई गई है या यह संपार्श्विक आधार पर आधारित है या कि यह एक मनमाना फैसला है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय उड़ीसा राज्य बनाम डॉ बीनापानी देवी* [(1967) 2 *एससीआर* 625: *एआईआर* 1967 *एससी* 1269: (1967) 2 *एलएलजे* 266] *और ए.के. क्रेपक बनाम भारत संघ* [(1969) 2 *एससीसी* 262: *एआईआर* 1970 *एससी* 150] *के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के बाद दिया गया था। वास्तव में, उक्त निर्णयों पर यह तर्क दिया गया था कि ऐसे मामले में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, तर्क स्वीकार नहीं किया गया। निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों को बाद के कई निर्णयों में स्वीकार किया गया और उनका पालन किया गया। कभी कोई असहमति नहीं हुई -* 1987 *तक भी नहीं* xxx xxx xxx

33. *इस अवस्था पर, हम स्पष्टीकरण का एक नोट संलग्न करना उचित*

समझते हैं। आम तौर पर प्रतिकूल टिप्पणियों को संप्रेषित करने की आवश्यकता होती है - गोपनीय रोल में की गई प्रत्येक अभियुक्ति, या अवलोकन की नहीं। ऐसी कई अभियुक्तियाँ, प्रेक्षण और टिप्पणियाँ हो सकती हैं, जो प्रतिकूल टिप्पणियाँ नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी एफ.आर. एफ.आर. 56(*जे*) *के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं या इसके अनुरूप कोई नियम। जिस उद्देश्य और उद्देश्य के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया है, उसे जे.एन. सिन्हा* [(1970) 2 *एससीसी* 458: (1971) 1 *एससीआर* 791] *में और ऊपर संदर्भित अन्य निर्णयों में भली-भांति बताया गया है।*

34. उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:

(i) *अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सज़ा नहीं है। इसका तात्पर्य कोई कलंक या दुर्व्यवहार का कोई संकेत नहीं है।*

(ii) *किसी सरकारी सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना लोकहित में है, यह राय बनने पर सरकार द्वारा आदेश पारित किया जाना है। यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया गया है।*

(iii) *अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। हालांकि उच्च न्यायालय या यह न्यायालय अपीलीय अदालत के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश इस प्रकार पारित किया गया है (क) दुर्भावनापूर्ण या (ख) कि यह बिना किसी सबूत पर आधारित है या (ग) कि यह मनमाना है - इस अर्थ में कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बनाएगा; संक्षेप में, यदि यह विकृत क्रम में पाया जाता है।*

(iv) *सरकार (या समीक्षा समिति, जैसा भी मामला हो) को मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा - निश्चित रूप से बाद के वर्षों के दौरान रिकॉर्ड और प्रदर्शन को अधिक महत्व देना होगा। इस प्रकार विचार किए जाने वाले रिकॉर्ड*

रिकॉर्ड में स्वाभाविक रूप से गोपनीय रिकॉर्ड/ चरित्र पंजियों में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की प्रविष्टियाँ शामिल होंगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी टिप्पणियों का महत्व खत्म हो जाता है, खासकर तब जब पदोन्नति योग्यता (चयन) पर आधारित हो, न कि वरिष्ठता पर।

(v) *अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल यह दर्शाने पर न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता कि इसे पारित करते समय असंसूचित प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था। वह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती।*

उपरोक्त (iii) *में उल्लिखित आधारों पर ही हस्तक्षेप की अनुमति है। इस पहलू पर ऊपर पैरा* 30 *से* 32 *में चर्चा की गई है।*

xxx xxx xxx

36. *जहां तक हमारे समक्ष अपीलों का सवाल है, उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक रिकॉर्ड और गोपनीय रिकॉर्ड पर गौर करते हुए राय दी है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न केवल उक्त प्रतिकूल टिप्पणियों पर बल्कि अन्य सामग्री पर भी आधारित था। दूसरे, यह भी पाया गया है कि उनके सामने रखी गई सामग्री इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराती है कि उक्त टिप्पणियां विधिवत या ठीक से दर्ज नहीं की गईं थीं। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दुर्भावना से ग्रस्त है या यह बिना किसी सबूत पर आधारित है या यह मनमाना है।*

अनिवार्य सेवानिवृत्ति में कोई नागरिक परिणाम शामिल नहीं है। सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले अपने द्वारा अर्जित किसी भी अधिकार को नहीं खोता है, जबकि सरकारी सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सेवा प्रदान की जाती है, सरकार को उन लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करके अपनी मशीनरी को सक्रिय करने और अधिक कुशल बनाने की शक्ति दी जाती है, जिन्हें उसकी राय में जारी नहीं रखा जाना चाहिए। जनहित में सरकार की सेवा में।

इसे भारत संघ बनाम कर्नल जे.एन. सिन्हा *(सुप्रा)* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा-*8, 9* और *10* में दिए गए दिए गए निर्णय में निम्नानुसार कहा गया है*:-*

> *8.* मूल नियम *56(i)*के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर दिया जाए। भारत संघ के अधीन सेवारत सरकारी कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद *310* में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करता है। लेकिन यह आनंद सिद्धांत अनुच्छेद *309* के तहत बनाए गए नियमों या कानून के साथ-साथ अनुच्छेद के तहत निर्धारित शर्तों के अध्यधीन है।
>
> *311.* नैसर्गिक न्याय के नियम सन्निहित नियम नहीं हैं और न ही उन्हें मौलिक अधिकारों के स्तर तक ऊपर उठाया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने ए.के.क्रेपक बनाम भारत संघ *[(1969) 2* एससीसी *262:* एआईआर *1970* एससी *150]* में देखा - प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना है या इसे नकारात्मक रूप से न्याय की अवमानना को रोकना है। ये नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे कानून का स्थान नहीं लेते, बल्कि उसे पूरक बनाते हैं। यह सच है कि यदि किसी वैधानिक प्रावधान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पढ़ा जा सकता है, तो अदालतों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि विधानमंडल और वैधानिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का इरादा रखते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई वैधानिक प्रावधान या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ से प्राकृतिक न्याय के किसी या सभी सिद्धांतों के आवेदन को बाहर करता है तो अदालत विधायिका या वैधानिक प्राधिकरण के आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकती है और संबंधित प्रावधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नहीं पढ़ सकती है। प्रदत्त शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए या नहीं, यह शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान के स्पष्ट शब्दों, प्रदत्त शक्ति की प्रकृति, जिस उद्देश्य के लिए इसे प्रदान किया गया है और उस शक्ति के प्रयोग के प्रभाव पर निर्भर करता है।
>
> *9.* अब मौलिक नियम *56(जे)* के स्पष्ट शब्दों पर आते हैं, यह कहता है कि उपयुक्त प्राधिकारी को एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है यदि उसकी राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। है। उपयुक्त प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकार पूर्ण हैं। उस शक्ति का प्रयोग नियम में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है, जिनमें से एक यह है कि संबंधित प्राधिकारी की राय होनी चाहिए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। यदि वह प्राधिकारी प्रामाणिक रूप से वह राय बनाता है, तो उस राय की सत्यता को अदालतों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। पीड़ित पक्ष यह दावा करने के लिए स्वतंत्र है कि अपेक्षित राय नहीं बनाई गई है या निर्णय संपार्श्विक आधार पर आधारित है या

यह एक मनमाना निर्णय है। प्रथम प्रतिवादी ने दुर्भावना के आधार पर सरकार द्वारा बनाई गई राय को चुनौती दी। लेकिन वह इस प्रयास में विफल हो गया है। उच्च न्यायालय ने उस दलील को नहीं माना. इस पर हमारे सम्मुख बल नहीं दिया गया. आक्षेपित आदेश पर इस आधार पर तर्क नहीं किया गया कि आवश्यक राय नहीं बनाई गई थी या जो राय बनाई गई थी वह मनमानी थी। प्रथम प्रतिवादी की सेवा की शर्तों में से एक यह है कि सरकार किसी कर्मचारी द्वारा पचास वर्ष पूरे करने के बाद किसी भी समय उसे सेवानिवृत्त करने का विकल्प चुन सकती है यदि उसे लगता है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में है। अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कारण वह सेवानिवृत्ति से पहले प्राप्त किए गए किसी भी अधिकार को नहीं खोता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति में कोई नागरिक परिणाम परिणाम शामिल नहीं है। उपरोक्त नियम *56(जे)* का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है। यह नियम संविधान के अनुच्छेद *310* में सन्निहित आनंद सिद्धांत के एक पहलू का प्रतीक मात्र है। नियम के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते समय उपयुक्त प्राधिकारी विभिन्न तथ्यों पर विचार कर सकता है। कुछ मामलों में, सरकार को यह महसूस हो सकता है कि किसी विशेष पद को धारण करने वाले से अधिक सक्षम अधिकारी द्वारा जनहित में अधिक उपयोगी ढंग से धारण किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो अधिकारी पद पद संभाल रहा है वह अक्षम न हो, लेकिन उपयुक्त प्राधिकारी अधिक कुशल अधिकारी रखना पसंद कर सकता है। यह भी हो सकता है कि कुछ कुछ प्रमुख पदों पर जनहित के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि कोई निःसंदेह योग्य और निष्ठावान व्यक्ति वहां मौजूद हो। इस तथ्य से नहीं किया जा सकता कि सभी संगठनों और उससे भी अधिक सरकारी संगठनों में अलाभकारी कर्मियों की अच्छी खासी संख्या होती है। उन्हें हटा हटा देना जनहित में है। नियम *56(जे)* व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी के अधिकारों और जनता के हितों के बीच संतुलन रखता है। जबकि सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सेवा की गारंटी दी जाती है, सरकार को उन लोगों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करके अपने तंत्र को सक्रिय करने और इसे और अधिक कुशल बनाने की शक्ति दी जाती है, जिन्हें उसकी राय में सार्वजनिक हित में नहीं होना चाहिए।

10. "यह सच है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सरकारी कर्मचारी पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन नियम यह बताता है कि ऐसी सेवानिवृत्ति केवल निर्धारित आयु प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है। इसके अलावा, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्जित किसी भी लाभ को नहीं खोता है। तीन महीने का नोटिस दिया जाता है ताकि वह अन्य उपयुक्त रोजगार ढूंढ़ सके।"

पंजाब राज्य बनाम गुरदास सिंह, **1998 (4) एससीसी 92** में रिपोर्ट किया गया, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया: -

"किसी सरकारी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का निर्णय

लेने से पहले, अधिकारियों को सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना आवश्यक है। सेवा के पूरे कार्यकाल के दौरान कर्मचारी के समग्र प्रदर्शन को देखना आवश्यक है कि क्या उसे सेवा में बनाए रखना लोक हित में है। कर्मचारी की सेवा के पूरे रिकॉर्ड में कोई भी असंचारित प्रतिकूल प्रविष्टियाँ भी शामिल होंगी।"

यूपी राज्य और अन्य बनाम बिहारी लाल, 1994 (सप्लीमेंट) 3 एससीसी 593 में रिपोर्ट किया गया, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया:-

"यह रिकॉर्ड का समग्र मूल्यांकन है, प्राधिकरण इस निर्णय पर पहुंचेगा कि क्या सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक हित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। एक उपयुक्त मामले में, कोई ठोस सामग्री नहीं हो सकती है लेकिन उसके आसपास बनी अधिकारी की प्रतिष्ठा ऐसी हो सकती है उनके आगे बने रहने से सार्वजनिक सेवा की दक्षता ख़तरे में पड़ जाएगी और अन्य लोक सेवकों में अनुशासनहीनता पैदा होगी। इसलिए, सरकार किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की अपनी शक्ति का वैध रूप से उपयोग कर सकती है। शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों सहित समग्र रिकॉर्ड पर भी विचार किया है, हालांकि तकनीकी कारणों से अपील या पुनरीक्षण पर इसे हटाया जा सकता है। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक सेवा में दक्षता बढ़ाने के लिए जनहित में लिया गया सच्चा निर्णय क्या है। शक्ति के किसी भी दुर्भावनापूर्ण प्रयोग या शक्ति के मनमाने प्रयोग के अभाव में, एक संभावित भिन्न निष्कर्ष किसी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आधार नहीं होगा।"

गुजरात राज्य और अन्य बनाम सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब एक उपयुक्त प्राधिकारी सद्भावना राय बनाता है कि सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में है, तो न्यायालय ऐसे आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

रजत बरन रॉय और पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, **रिट याचिका संख्या 578/1998 (डायरी संख्या 16843/1998)13.04.1999** को निर्णय लिया गया, में माननीय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए सार्वजनिक हित में और इसके लिए, प्राधिकरण को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसा ऐसा आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त भौतिक विवरण थे।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाम एचसी (जीडी) ओम प्रकाश, 2012 की सिविल अपील संख्या 5428 पर 4.2.2022 को निर्णय लिया गया, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे निम्नानुसार माना गया है:-

> "6. बैकुंठ नाथ दास मामले में फैसले के बाद, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने डाक और टेलीग्राफ बोर्ड बनाम सी.एस.एन. मूर्ति के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में कहा कि अदालतें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेंगी यदि यह प्रामाणिक रूप से और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर तय की गई हो। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:
>
> "5. ....क्या कर्मचारी का आचरण ऐसा है कि इस तरह के निष्कर्ष को उचित ठहराया जा सके, यह मुख्य रूप से विभागीय अधिकारियों को तय करना है। अपराध की प्रकृति और क्या यह इस स्तर का है कि कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आवश्यकता हो, इस पर मुख्य रूप से सरकार को निर्णय लेना है। यदि प्रामाणिकता और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय लिया जाए तो अदालतें इस शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। वर्तमान मामले में किसी दुर्भावना का आग्रह नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय का एकमात्र सुझाव यह है कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री का खुलासा नहीं किया गया है जो प्रतिवादी के खिलाफ की गई कार्रवाई को उचित ठहराए। इस बात पर हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। हमारी राय में, ऐसी सामग्री थी जो दर्शाती है कि समीक्षाधीन अवधि के पिछले दो वर्षों में याचिकाकर्ता की दक्षता कम हो रही थी और इसलिए, हमारे लिए विभाग के निष्कर्ष को दुर्भावनापूर्ण, विकृत, मनमाना या अनुचित करार देना संभव नहीं है।"
>
> 7. भारत संघ बनाम दुलाल दत्त, 1993 (2) एससीसी 179 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय की तीन न्यायाधीशों

की पीठ ने भारतीय रेलवे में स्टोर नियंत्रक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की जांच की। यह माना गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सज़ा का आदेश नहीं है। यह सरकार का विशेषाधिकार है लेकिन यह तत्वों तत्वों पर आधारित होना चाहिए और सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाना चाहिए और इसका स्पष्टीकारक आदेश होना आवश्यक नहीं है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"18. यह देखा जाएगा कि ट्रिब्यूनल ने मामले की परिस्थितियों में यह मानने में पूरी तरह से गलती की है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए एक स्पष्टीकारक आदेश होना चाहिए था। यह न्यायालय, आर.एल. बुटेल बनाम भारत संघ [(1970) 2 एससीसी 876] और भारत संघ बनाम जे.एन. सिन्हा [(1970) 2 एससीसी 458] के मामले से बार-बार जोर दे रहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सज़ा का आदेश नहीं है। यह वास्तव में सरकार का विशेषाधिकार है लेकिन यह सामग्री पर आधारित होना चाहिए और सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित होना चाहिए। अक्सर, न्यायालय द्वारा पूछताछ करने पर सरकार सामग्री का खुलासा कर सकती है लेकिन यह उस कहावत से बहुत अलग है कि आदेश स्पष्टीकारक आदेश होना चाहिए। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के किसी भी आदेश को स्पष्टीकारक आदेश होना आवश्यक नहीं है। ट्रिब्यूनल के आदेश से ही यह स्पष्ट है कि सरकार के पास समीक्षा समिति की रिपोर्ट थी, फिर भी उसने प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत करना उचित समझा। आदेश को दुर्भावनापूर्ण या मनमाना कानून नहीं कहा जा सकता।"

भारत संघ बनाम वी.पी. सेठ (सुप्रा) में, बैकुंठ नाथ दास और अन्य निर्णयों पर भरोसा करते हुए, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार माना गया था:

"3. इन सिद्धांतों को आगामी निर्णय में अनुमोदन सहित दोहराया गया। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल दुर्भावना, मनमानी या विकृति के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के के बाद से ऑडी अल्टरम पार्टम का नियम लागू नहीं होता है। यह

दंडात्मक प्रकृति का नहीं है। इस प्रकार इस न्यायालय के दो निर्णयों से कानून की स्थिति तय हो गई है, हम समझते हैं कि ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह उक्त दो निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है।"

यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा ट्रिब्यूनल द्वारा पारित दिनांक 7.8.2020 के आदेश के साथ-साथ प्रतिवादियों द्वारा पारित दिनांक 29.3.2018 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा नियमावली 1958 के नियम 16(3) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इस आदेश में ट्रिब्यूनल द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी है।

याचिकाकर्ता भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। प्रतिवादियों ने 1958 के नियमों के नियम 16(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29.3.2018 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त आदेश यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"अखिल भारतीय सेवा *(*मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ*)* नियम, *1958* के नियम *16* के उप-नियम *3* के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से श्री इंदु कुमार भूषण, आईपीएस *(*आरजे*:* *1989),* भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य, राजस्थान कैडर के सदस्य, जिन्होंने *25* वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, को नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर सार्वजनिक हित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त किया जाता है।

2. तीन महीने की अवधि के लिए उसके वेतन और भत्ते की कुल राशि के बराबर राशि का एक चेक, जिसकी गणना उसी दर पर की गई थी जिस पर वह इस आदेश की तारीख से ठीक पहले आहरित कर रहा था।

राष्ट्रपति के नाम से और उनके आदेश द्वारा

(मुकेश साहनी)

अवर सचिव, भारत सरकार"

उपरोक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी गई और ट्रिब्यूनल ने दिनांक 7.8.2020 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज कर दिया।

उपरोक्त सभी आदेशों को याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

मामले को आगे बढ़ाने से पहले, 1958 के नियमों के नियम 16(3) को उद्धृत करना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है:-

> "केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसे सदस्य को कम से कम तीन महीने पहले लिखित नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन और भत्ते देने के बाद, सार्वजनिक हित में सेवा से सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकती है:-
>
> *(i)* समीक्षा के बाद जब ऐसा सदस्य अर्हक सेवा के *15* वर्ष पूरे कर लेगा; या
>
> *(ii)* समीक्षा के बाद जब ऐसा सदस्य *25* वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेता है या *50* वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, जैसा भी मामला हो; या
>
> *(iii)* यदि ऊपर *(i)* या *(ii)* में निर्दिष्ट समीक्षा नहीं की गई है, तो समीक्षा के बाद किसी अन्य समय पर जब केंद्र सरकार ऐसे सदस्य के संबंध में उचित समझे।
>
> स्पष्टीकरण:- उप-नियम *(3)* के प्रयोजनों के लिए, "समीक्षा" का अर्थ है सेवा में आगे बनाए रखने के लिए ऐसे सदस्य की उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में सेवा के सदस्य के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा, जो प्रत्येक सदस्य की नियमित रूप से की जानी है। ऐसी सेवा, सबसे पहले, उसकी *15* साल की अर्हक सेवा पूरी होने के बाद, और दूसरी, उसकी *25* साल की अर्हक सेवा पूरी होने के बाद या उसके *50* वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जैसा भी मामला हो, या यदि समीक्षा में संदर्भित है इस उप-नियम के खंड *(i)* या *(ii)* ऐसे सदस्य के संबंध में आयोजित नहीं किए गए हैं, ऐसी समीक्षा किसी अन्य समय पर की जा सकती है जैसा केंद्र सरकार उचित समझे।""

समीक्षा समिति का गठन किया गया और समीक्षा समिति के समक्ष याचिकाकर्ता सहित उनके बारे में सभी तथ्य रखे गए, संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टियाँ प्रस्तुत की गईं। अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण तथ्यों एवं सामग्री पर विचार करने के बाद समीक्षा समिति द्वारा एक व्यक्तिपरक निर्णय पर पहुंचा गया और जनहित में याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की गई, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता की जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति को निलंबित कर दिया गया।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सज़ा नहीं है और न ही यह किसी कर्मचारी-याचिकाकर्ता पर कोई कलंक लगाता है। जनहित में सरकार का व्यक्तिपरक निर्णय याचिकाकर्ता के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद आया, जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंड नहीं है।

याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 29.3.2018 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का पूरा सर्विस रिकॉर्ड रिव्यू कमेटी के सामने रखा गया। समीक्षा समिति ने पूरे रिकॉर्ड की जांच की और निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की: -

> "समिति ने सभी अधिकारियों के एपीएआर डोजियर, व्यक्तिगत फाइलों और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेजों की जांच की। श्री इंदु कुमार भूषण के एपीएआर के अवलोकन पर, यह पाया गया कि श्री इंदु कुमार भूषण की समग्र ग्रेडिंग "अच्छी" से "बहुत अच्छी" तक थी और अन्य अधिकारियों की तुलना में काफी कमजोर थी। सभी उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, समिति ने विशेष रूप से श्री भूषण से संबंधित रिकॉर्ड की जांच उनके एसीआर/एपीएआर के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों में परिलक्षित उनके औसत प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए विस्तार से करना उचित समझा। रिकॉर्ड से, समिति ने श्री इंदु कुमार भूषण के अनुचित, असामान्य और अनुचित व्यवहार को दर्शाने वाली कुछ घटनाएं देखीं: -
>
> *(1)* उन्होंने जीएडी अधिकारियों के साथ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया किया और तत्कालीन विशेष सचिव, जीएडी ने उनसे माफी मांगने की मांग मांग की

(2) दिनांक *06-07-1999* के आदेश द्वारा उन्हें एस.पी. डूंगरपुर के पद से स्थानांतरित कर दिया गया। डूंगरपुर से अपने स्थानांतरण पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को आत्महत्या करने की धमकी करने भरा पत्र लिखा।

.

(3) श्री इंदु भूषण को समय से पहले आईटीबीपी से राजस्थान कैडर में वापस भेज दिया गया और उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य पद पर तैनात करने का राजस्थान सरकार का अनुरोध भी भारत सरकार ने ठुकरा दिया।

(4) समय पर कार्यालय आने के लिए कहने पर तत्कालीन डी.जी.जेल के विरुद्ध असंसदीय भाषा का प्रयोग।

(5) श्री इंदु भूषण *22/06.2015* से *07.09.2015* तक एडीजी *(*जेल*)* के पद पर तैनात थे, इस कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कदाचार और दुर्व्यवहार की गंभीर रिपोर्टें डी.बी. जेल को भेजी गईं।

(6) उन्हें अनुशासनहीनता के कारण एमसीटीपी चरण *V* प्रशिक्षण के दौरान एसवीपीएनपीए से राज्य में वापस भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल के साथ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। (टाइम्स ऑफ इंडिया, *21* सितम्बर)।

(7) उन्होंने *26* दिसंबर *2011* से *29* फरवरी *2016* तक आरपीए में सरकारी आवास में रहते हुए मकान का किराया नहीं दिया। इसके लिए उन्हें *1,45,323/-* रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया था जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। उन्होंने अनाधिकृत रूप से आरपीए में एक अतिरिक्त घर पर भी कब्जा कर लिया और *13* वर्षों से अधिक समय तक किराया नहीं दिया।

हालाँकि इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन समय-समय समय पर उनके व्यवहार के बारे में विभिन्न समाचार त्रों में प्रकाशित खबरें खबरें भी श्री इंदु भूषण के असामान्य और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाती हैं और अधिकारी के दिमाग और व्यक्तित्व गुणों के बारे में

जानकारी देती हैं। इनका विवरण इस प्रकार है*:*

(1) पुलिस थाना, सिन्धी कैम्प, जयपुर में एक व्यक्ति को रिवाल्वर हथियार से धमकाया।

(2) दिल्ली की एक फर्म द्वारा सोशल मीडिया पर दिए जा रहे प्रेजेंटेशन के दौरान एक साथी आईपीएस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए, जिससे मीडिया के साथ-साथ अन्य सहयोगियों के सामने आईपीएस अधिकारियों की छवि खराब हुई। *(*टाइम्स ऑफ इंडिया, *16* जून *2017,* राजस्थान पत्रिका जून, *2016* पेज*-2)*।

(3) हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो कि परिपत्र संख्या एफ*.3(I)* डीओपी*/*आईएनजी*/2004* दिनांक *12.10.2017* का उल्लंघन है।

इसके अलावा समिति को सूचित किया गया कि उनके खिलाफ निम्नलिखित आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं*: -*

(क) *25* अगस्त *2015 -* आईपीसी की धारा *504, 3(i) (x)* एससी*/*एसटी अधिनियम के तहत एफआईआर *813/15,* थाना, वैशाली नगर, जयपुर *(*दक्षिण*) (*डॉ.कमलेश कुमार, प्रभारी सेंट्रल जेल, जयपुर के साथ दुर्व्यवहार*)* - इस मामले में एफआर दी गई है लेकिन शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दायर की है।

(ख) *21* अप्रैल *2015 -* आईपीसी की धारा *374, 384* के तहत एफआईआर *325/15,* पीएस, वैशाली नगर, जयपुर *(*दक्षिण*) (*वाहन छीन लिया और अपने घर पर काम कर रहे लेबर के साथ दुर्व्यवहार किया*)* - बंद कर दी गई।

(ग) *10* मई *2015 -* आईपीसी की धारा *341, 323, 34* के तहत, पीएस, बेहरामपुर, जिला एफआईआर *591/14*। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल *(*उचित अनुमति के साथ चुनावी रैली कर रहे कार्यकर्ताओं को परेशान करना और घायल करना)। इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। *22* जुलाई *2013 -* आईपीसी की धारा *341, 323, 504, 379* के

तहत एफआईआर *202/13, 3* एससी/एसटी एक्ट, थाना शास्त्री नगर, जयपुर *(उत्तर)* सीटी चालक गोपाल मीना *5372* के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट कर घायल करने के संबंध में। इस मामले में आरोप-पत्र के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

उपरोक्त अधिकारियों के सभी अभिलेखों की जांच के बाद समिति निम्नानुसार अनुशंसा करती है*:-*

*"*समिति की राय है कि श्री इंदु कुमार भूषण ने कई मौकों पर कार्यालय के लिए अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित किया है, और उनके वरिष्ठों के साथ-साथ कनिष्ठों के साथ भी तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, और उनका कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं रहा है। इसलिए समिति ने पाया कि श्री इंदु कुमार भूषण, आईपीएस *(*आरआर*:89)* सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य हैं। समिति ने शेष बीस *(92)* आईपीएस अधिकारियों को सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त पाया।*"*

समीक्षा समिति का निर्णय पूरी तरह से एक स्वतंत्र कार्यवाही है और याचिकाकर्ता के सभी सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए, समीक्षा समिति द्वारा एक व्यक्तिपरक निर्णय दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए मामले की सिफारिश की गई थी और उसी के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता को समय से पहले सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति के विभिन्न पहलू हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश सरकारी कर्मचारी के समग्र सेवा रिकॉर्ड को देखकर पारित किया जा सकता है। प्रशासन की दक्षता में सुधार की दृष्टि से जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश भी पारित किया जा सकता है।

कुछ न्यूनतम निर्धारित सेवाओं के बाद और नियमानुसार निर्धारित आयु के बाद कर्मचारी को सेवाओं में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह उसके संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड और सेवाओं में उसकी उपयोगिता तथा बाद के वर्षों के दौरान उसके समग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उसे सेवाओं में जारी रखे या नहीं। केंद्र सरकार के कर्मचारी के समग्र मूल्यांकन में, भले ही पुलिस द्वारा दो एफआईआर में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो, प्रतिवादी संख्या 1 हमेशा इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है

कि संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड को देखकर और याचिकाकर्ता की उपयोगिता को देखते हुए, उसे सेवाओं से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यह एक जटिल निर्णय है और समीक्षा समिति को विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होगा। जो लोग अपने सेवाकाल के दौरान सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। यह शक्ति सरकार को अपने तंत्र को सक्रिय करने और सार्वजनिक हित में उन लोगों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करके अधिक कुशल बनाने के लिए दी गई है, जिन्हें उसकी राय में सेवाओं में बने नहीं रहना चाहिए।

जो देखा जाना है वह किसी कर्मचारी के कार्यनिष्पादन और सेवाओं में उसकी उपयोगिता का समग्र मूल्यांकन है, न कि किसी एक या दो मामलों में और उन मामलों में लिया गया निर्णय। यह राय समीक्षा समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि है। वर्तमान मामले में, 1958 के नियमों के नियम 16(3) के तहत निर्णय लेते समय समीक्षा समिति द्वारा कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेते समय समीक्षा समिति की ओर से कोई मनमानी नहीं की गई है। निर्णय संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, याचिकाकर्ता के प्रदर्शन और भारत संघ की सेवा में याचिकाकर्ता की उपयोगिता पर आधारित है और याचिकाकर्ता के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, समीक्षा समिति द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त की गई है। हम समीक्षा समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि के विरुद्ध अपील में पर विचार नहीं कर रहे हैं।

समीक्षा समिति के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं है। समीक्षा समिति ने याचिकाकर्ता के आचरण सहित याचिकाकर्ता की सेवा का पूरा रिकॉर्ड देखा और समीक्षा समिति की राय थी कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को जारी रखने की अब आवश्यकता नहीं है और उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने में समीक्षा समिति की ओर से कोई दुर्भावना, कोई मनमानी या कोई विकृति नहीं है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई सजा नहीं है। इस प्रकार अनिवार्य सेवानिवृत्त हुआ सरकारी सेवक उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उसके द्वारा अर्जित कोई भी लाभ नहीं खोता है।

हालांकि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ द्वेष और दुर्भावना के आरोप

लगाए हैं, लेकिन वह अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश करके इसे स्थापित करने में विफल रहा है।

"अजीत कुमार नाग बनाम महाप्रबंधक (पीजे), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया और अन्य, (2005) 7 एससीसी 764 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आदेश को दुर्भावनापूर्ण साबित करने का बोझ आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर है और यह बोझ "बहुत भारी" है। प्रशासन के पक्ष में प्रत्येक धारणा है कि शक्ति का प्रयोग सद्भावना और सद्भावना से किया गया है। यह याद रखना चाहिए कि दुर्भावनापूर्ण आरोप अक्सर लगाए जाने की तुलना में अधिक आसानी से लगाए जाते हैं और ऐसे आरोपों की गंभीरता उच्च स्तर की विश्वसनीयता के प्रमाण की मांग करती है। जैसा कि कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति ने ***गुलाम मुस्तफा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1976 (1) एससीसी 800 पैरा 2 में रिपोर्ट किया गया, में कहा है: "यह (दुर्भावनापूर्ण) एक हारे हुए वादी की आखिरी शरण है।"***

यह स्थापित कानून है कि दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाना वास्तव में लगाने की तुलना में आसान है। दुर्भावनापूर्ण आरोपों की पुष्टि तात्विक तथ्यों के संक्षिप्त बयानों से की जानी चाहिए जो आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं। यहां इस मामले में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं लेकिन कोई ठोस सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, जो किसी भी विश्वास को प्रेरित करती हो।

समीक्षा समिति ने बिना किसी दुर्भावना, मनमानी और विकृति के 1958 के नियमों के नियम 16(3) के तहत प्रामाणिक राय बनाई है। इसलिए, गुण-दोष के आधार पर समीक्षा समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि वाले निर्णय की सत्यता को इस अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निशा प्रिया भाटिया (सुप्रा) में पैराग्राफ 54 और 71 में निम्नानुसार रखा गया है:

> *"54.* वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, हम उपरोक्त श्रृंखला से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को सामने लाना उचित समझते हैं। घटनाओं के उपरोक्त अनुक्रम से आंतरिक संचार की श्रृंखला का पता चलता है जिसके बाद अंततः *18-12-2009* का आदेश पारित किया गया था अर्थात सचिव *(*आर*)* द्वारा पीएमओ को भेजा गया गुप्त नोट, दिनांक *11-5-2009,* पत्र दिनांक *21-7-2009* द्वारा भारत के तत्कालीन

सॉलिसिटर जनरल की राय, विधि कार्य विभाग, केंद्रीय विधि मंत्रालय की राय राय और न्यायमूर्ति और पीएमओ नोट, जिसमें नियम *135* के आह्वान को एकमात्र व्यवहार्य विकल्प के रूप में निर्धारित किया गया था, एक साथ मिलकर जांच की एक पूरी श्रृंखला का गठन करते हैं, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सवाल पर प्रतिवादियों द्वारा उचित विवेक के आवेदन को प्रकट करता है। यह स्थापित कानून है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और यह विवेक का का इस्तेमाल न करने या दुर्भावना जैसे सीमित आधारों पर ही स्वीकार्य है। प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य का आधार लिया जा सकता है है *[*प्यारे मोहन लाल बनाम झारखंड राज्य, *(2010) 10* एससीसी *693: (2011) 1* एससीसी *(*एल एंड एस*) 550]*। उपरोक्त उद्धृत घटनाओं का सेट इतना स्पष्ट है कि यह हमें यह मानने के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं छोड़ता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई ही उचित विकल्प था। था। यह मानते हुए कि कोई अन्य विकल्प भी संभव था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपीलकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का सक्षम प्राधिकारी का निर्णय बाहरी, दुर्भावनापूर्ण, विकृत, अनुचित या मनमाने विचारों से प्रेरित था। उचित सोच-विचार की शर्त पूरी होती दिख रही है क्योंकि *22-9-2008* से *18-12- 2009* के *15* महीनों के दौरान संगठन और पीएमओ के बीच चर्चाओं, विचार-विमर्श और परामर्शों की एक एक श्रृंखला के बाद यह निर्णय लिया गया है।*"*

राम मूर्ति यादव बनाम उ.प्र. राज्य (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा-6 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:-

"6. अपीलकर्ता के सेवा रिकॉर्ड की जांच स्क्रीनिंग कमेटी, पूर्ण न्यायालय और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा भी की गई है। नियोक्ता की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण और प्रतिबंधित है। केवल अगर यह पाया जाता है कि यह मनमाने या मनमौजी आधार पर आधारित है, दुर्भावना से प्रेरित है, प्रासंगिक सामग्रियों की अनदेखी करता है, तो

हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश हो सकती है। न्यायिक समीक्षा में अदालत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में निर्णय नहीं दे सकती। अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उपयोग नहीं होता है।"

उड़ीसा राज्य बनाम राम चंद्र दास, (1996) 5 एससीसी 331 में रिपोर्ट किया गया, के पैरा-7 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार यह निर्णय लिया गया है:-

"7..... उद्देश्य सदैव जनहित होता है। अहम सवाल यह है कि क्या सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार किया गया या नहीं*?* यह देखना अदालत/न्यायाधिकरण का काम नहीं है कि सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का सरकार का निर्णय उचित है या नहीं। यह सरकार पर निर्भर है कि वह इस पर विचार करे और इस संबंध में उचित निर्णय ले। जैसा कि पहले कहा गया है, यह स्थापित कानून है कि सरकार को सेवा के संपूर्ण रिकॉर्ड पर विचार करना आवश्यक है। केवल इसलिए कि प्रतिकूल प्रविष्टियाँ दिए जाने के बाद भी पदोन्नति दी गई है, यह ध्यान देने का आधार नहीं हो सकता कि सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता। ट्रिब्यूनल की राय के अनुसार साक्ष्य अस्वीकार्य या अप्रासंगिक नहीं होता है। प्रासंगिक बात यह होगी कि क्या रिकॉर्ड की उस स्थिति के आधार पर एक उचित विवेकशील व्यक्ति के रूप में सरकार या सक्षम अधिकारी उस निर्णय पर पहुंचेंगे। हम पाते हैं कि पदोन्नति के बाद उसी सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता है, केवल उसे आगे पदोन्नति से वंचित करने के लिए, यदि कोई हो। लेकिन वह सामग्री निस्संदेह सरकार के पास पेंशन के लिए आवश्यक सेवा अवधि या सेवा की योग्य अवधि प्राप्त करने के बाद सरकारी कर्मचारी को सेवा में जारी रखने की समग्र समीचीनता या आवश्यकता पर विचार करने के लिए उपलब्ध होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ पदोन्नति के बाद ही की गई थीं, पदोन्नति से पहले नहीं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई सज़ा नहीं है। वह सभी पेंशन लाभों का हकदार है।*"*

याचिकाकर्ता की इस दलील में कोई दम नहीं है कि उनका अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 29.03.2018, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.06.2012 के दिशानिर्देशों का का पालन किए बिना जारी किया गया था। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि केवल संदिग्ध निष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति को ही समय से पहले सेवानिवृत्ति दी जा सकती है जो अपनी उपयोगिता खो चुके हों। और इस तर्क में भी कोई दम नहीं है कि जिस व्यक्ति की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय बचा हो, उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से अधिक का समय था। डीओपीटी के दिशानिर्देशों का का पालन करने के बाद, अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किया गया। दिनांक 29.03.2018 का आक्षेपित आदेश प्राधिकारियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया का परिणाम है और उस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाया गया है। याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि उनकी एसीआर एसीआर 'औसत' और 'कमजोर' की तुलना में 'अच्छी' और 'बहुत अच्छी' थीं। अन्य लोगों की एसीआर और उनका आचरण भी असंतोषजनक था, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता समानता के सिद्धांत को लागू करके ऐसे मामलों में किसी भी नकारात्मक समानता का दावा नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से यह कहना भी गलत है कि सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 29.03.2018 को पारित आदेश पारित करने से पहले अपने विवेक का का प्रयोग नहीं किया है। याचिकाकर्ता की ओर से यह कहना भी गलत है कि सक्षम प्राधिकारी ने केवल समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया है। है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीआइजी (जेल) और के खिलाफ याचिकाकर्ता के असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन और आचरण पर विचार करने के बाद बाद याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न अवसरों पर इस्तेमाल की गई असंसदीय भाषा और उच्च जिम्मेदार अधिकारियों और समीक्षा समिति के सदस्यों की रिपोर्ट को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया गया। याचिकाकर्ता अपने खिलाफ प्रतिवादी नंबर 4 की दुर्भावना और दुर्भावना को साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने केवल द्वेष के आरोप लगाए हैं लेकिन अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करके इसे साबित करने में असफल रहे। उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने मात्र से उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती। एक एक के बाद एक, उनके खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की गईं और यहां तक कि उन मामलों में शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ विरोध याचिकाएं भी प्रस्तुत की गईं,

गईं, जिनमें अंतिम नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थीं।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई दम नहीं है कि कुल मिलाकर 21 पुलिस अधिकारियों के मामले समीक्षा समिति को भेजे गए थे और समीक्षा समिति ने केवल याचिकाकर्ता का चयन किया और उसे समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी लेकिन बाकी 20 व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2 मार्च 2022 को निर्णित 2022 की सिविल अपील संख्या 2049-2050 में उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रजित सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि समानता के सिद्धांत को लागू करके ऐसे मामलों में किसी भी नकारात्मक समानता का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार, न्यायाधिकरण के निष्कर्ष ठोस तर्क पर आधारित हैं।

उच्च पुलिस अधिकारी के आचरण को परखने का मापदण्ड आवश्यक रूप से कठोर होना चाहिए। वर्दीधारी सेवाओं में अनुशासन से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां इस मामले में, याचिकाकर्ता, जो भारतीय पुलिस सेवा में एक उच्च अधिकारी था, के खिलाफ अनुचित और अवांछित उदाहरणों की एक श्रृंखला है, अर्थात मुख्यमंत्री को आत्महत्या करने की धमकी देने का आचरण और जीएडी अधिकारियों, तत्कालीन डी.जी. (जेल), तेलंगाना के राज्यपाल के खिलाफ असंसदीय भाषाओं का उपयोग करने के अनुचित कृत्य, थाने में रिवॉल्वर दिखाकर एक व्यक्ति को धमकाना, साथी आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ गाली-गलौज करना और बेबुनियाद आरोप लगाना, विभाग के सर्कुलर के खिलाफ 'प्रेस कॉन्फ्रेंस' करना, चार आपराधिक मामलों में बार-बार शामिल होना, समीक्षा समिति को इस निष्कर्ष पर लाया कि याचिकाकर्ता का आचरण उन्होंने अपने व्यवहार को एक अशोभनीय अधिकारी के रूप में प्रदर्शित किया है क्योंकि उनके वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के साथ तनावपूर्ण संबंध थे और उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इसलिए, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित और सही थी कि याचिकाकर्ता सेवा में बने रहने के लिए 'अयोग्य' है। बहस के दौरान भी, याचिकाकर्ता ने इस अदालत से ट्रिब्यूनल के उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिन्होंने उसके मूल आवेदन को खारिज कर दिया था। इस तरह का तर्क उनके आचरण को दर्शाता है कि उन्हें न्यायाधिकरण/ न्यायालयों के प्राधिकार के प्रति कम से कम सम्मान है।

इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रतिवादियों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी बाहरी, दुर्भावनापूर्ण, विकृत, अनुचित या मनमाने विचारों से प्रेरित थे।

1958 के नियमों के नियम 16(3) के तहत निर्णय लेते समय समीक्षा समिति और अधिकारियों द्वारा कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं की गई थी। समीक्षा समिति के आदेश में कोई विकृति और मनमानी नहीं है।

निर्णय पूरे सेवा रिकॉर्ड, याचिकाकर्ता के प्रदर्शन और प्रतिवादियों की सेवा में याचिकाकर्ता की उपयोगिता पर आधारित है और याचिकाकर्ता के खिलाफ तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, समीक्षा समिति द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचा गया है। हम समीक्षा समिति की व्यक्तिपरक संतुष्टि के खिलाफ अपील की समीक्षा नहीं कर रहे

समीक्षा समिति उच्च एवं जिम्मेदार अधिकारियों से बनी थी। शक्ति केवल सरकार में निहित है, छोटे अधिकारियों में नहीं। इसलिए, सरकार ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, सरकार को सरकार में एक निश्चित अवधि तक सेवा करने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के लिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 1958 के नियम के नियम 16 (3) के तहत याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया है। ।

इस प्रकार, मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता को समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, 1958 के नियमों के नियम 16 (3) के तहत सार्वजनिक हित में, उचित विवेक के बाद, अधिकारियों द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। संपूर्ण सामग्री व्यक्तिपरक संतुष्टि के साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का आचरण अच्छा नहीं था और पूरे सेवा कार्यकाल में उसका कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसके कारण 1958 के नियमों के नियम 16(3) के तहत उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति जरूरी हो गई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश बिना विवेक का प्रयोग किए या रिकॉर्ड पर विद्यमान अपर्याप्त सामग्री के पारित किया गया था या यह जनहित में नहीं था।

हम ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.8.2020 के आदेश में दिए गए कारणों से पूरी तरह सहमत हैं।

उपरोक्त तथ्यों, कारणों और न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे याचिकाकर्ता के लिए किसी भी रूप में मददगार नहीं हैं।

इसलिए, इस रिट याचिका में कोई तथ्य नहीं है और इसलिए इसे लंबित आवेदन(आवेदनों) के साथ खारिज किया जाता है।

(**अनूप कुमार ढंड़**), **न्यायमूर्ति** (**पंकज भंडारी**), **न्यायमूर्ति**

S h a m a N K/59

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।